

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER **दैनिक भास्कर** नई दिल्ली, सोमवार 20 मार्च, 2023 DATED \_\_\_\_\_

## **भास्कर खास • देसी घास से तैयार होगा 171 एकड़ में फैला दिल्ली का तीसरा अंतरराष्ट्रीय मानक वाला मैदान खुशखबरी: दिल्ली को एक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स, 250 करोड़ की लागत से साल के अंत तक पूरा हो सकता है काम**

**जिम, स्विमिंग पूल, रेस्त्रां  
और कान्फ्रेंस जैसी कई  
और सुविधाएं मिलेंगी**

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

दिल्लीवालों को इस साल के अंत तक एक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स मिल जाएगा। इस गोल्फकोर्स को डीडीए की ओर से 250 करोड़ के लागत से तैयार की जा रही है। इस गोल्फ कोर्स क्लब में आने वाले लोगों को जिम, स्विमिंग पूल, रेस्त्रां, कान्फ्रेंस, क्लब हाउस, गोल्फ अकादमी, ड्राइविंग रेंज जैसी कई और भी सुविधाएं मिलेंगी। इस गोल्फ कोर्स का निर्माण द्वारका के

सेक्टर-24 में हो रहा है और इसमें 18 होल्स होंगे। इसका काम दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

डीडीए के अधिकारियों के अनुसार, यह 171 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। मूल योजना के तहत, इसका निर्माण दो चरणों में पूरा होना था। पहले चरण में गोल्फ कोर्स की जमीन पर मिट्टी, हरियाली व सिंचाई से जुड़े काम होते और दूसरे चरण में यहां गोल्फ अकादमी, क्लब हाउस व ड्राइविंग रेंज जैसी अन्य सुविधाओं का विकास होता। क्लब हाउस में जिम, स्विमिंग पूल, रेस्त्रां, कान्फ्रेंस हाल सहित अन्य सुविधाएं यहां आने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होती।

**ये डीडीए का तीसरा गोल्फ कोर्स, इसमें झील का भी होगा निर्माण**

इस गोल्फ कोर्स में झील का निर्माण भी किया जाना है। कुल तीन झील यहां बनाए जा रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग जिनमें वर्षा का पानी एकत्र होगा। अभी इस समय दिल्ली में डीडीए के अधीन दो गोल्फ कोर्स कुतुब गोल्फ कोर्स व भलस्वा गोल्फ कोर्स हैं। इसके अलावा दिल्ली में जाकिर हुसैन मार्ग पर दिल्ली गोल्फ कोर्स है। छावला में भी सीमा सुरक्षा बल परिसर में एक गोल्फ कोर्स है। धौलाकुआं में भी दिल्ली छावनी इलाके में एक गोल्फ कोर्स है। द्वारका सेक्टर 24 का गोल्फ कोर्स डीडीए का तीसरा गोल्फ कोर्स होगा।

**अब एक ही चरण में होगा निर्माण कार्य**

दोनों चरणों के लिए अलग-अलग बजट का प्रावधान था। पहले चरण के बाद दूसरे चरण से जुड़ा काम होता, लेकिन अब जबकि इस परियोजना में देरी हो चुकी है, डीडीए ने तय किया कि दोनों चरण से जुड़े काम एक साथ होंगे और यह इस साल के अंत तक पूरे होने हैं। इसके तहत, सिंचाई के लिए गोल्फ कोर्स के विभिन्न हिस्सों में पानी की पाइपलाइन डालने का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है।

**मैक्सिकन की जगह देसी घास पर जोर**

अधिकारियों का कहना है कि इस कोर्स के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मैक्सिकन घास के बजाय देशी घास का इस्तेमाल करने पर हमारा जोर है। इसकी वजह देश की जलवायु के अनुरूप इस घास का उपयुक्त होना है। जहां विदेशी घास का विकास तेजी से होता है। वहीं, देसी घास का विकास उतनी तेजी से नहीं होता है। इससे मेंटेनेंस में सुविधा होगी।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | शनिवार, 18 मार्च 2023

मेरी कॉलोनी : दिल्ली : मेरा शहर

## द्वारका की सोसायटियों में रहने वालों को बदबू से मिलेगी राहत बरसाती नालों और नजफगढ़ ड्रेन में नहीं गिरेगा गंदा पानी

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

द्वारका के विभिन्न इलाकों से गुजरने वाले बरसाती नालों में अब सीवर का गंदा पानी नहीं गिरेगा। इसके लिए डीडीए सीवर लाइन बिछा रहा है। सीवर का गंदा पानी नई पाइपलाइन से होते हुए सोवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में जाएगा। प्लांट में इसे ट्रीट कर इसका इस्तेमाल सिंचाई आदि के कामों में किया जाएगा। बचे हुए पानी को यमुना का फ्लो बढ़ाने के लिए नजफगढ़ ड्रेन में डाला जाएगा। साथ ही बरसाती नालों से आ रही बदबू से सोसायटी वालों को राहत मिलेगी।

डीडीए अधिकारी के अनुसार सीवर लाइन के बिछने से यमुना में नजफगढ़ नाले के माध्यम से जा रही गंदगी भी कम होगी। इस साल के अंत तक यह काम

पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी के अनुसार 1995 में डीडीए ने बरसाती नाले के रूप में ट्रंक ड्रेन दो और पांच बनाई थी। आबादी बढ़ने की वजह से इन बरसाती नालों में सीवर का पानी भी आने लगा।

### क्या हैं हालात

- 1995 में डीडीए ने बरसाती नाले के रूप में ट्रंक ड्रेन दो और पांच बनाई थी
- आबादी बढ़ने की वजह से इन बरसाती नालों में सीवर का पानी भी आने लगा

5.2 किमी लंबी ट्रंक ड्रेन दो द्वारका सेक्टर-8 से सेक्टर-24 में जाकर नजफगढ़ नाले में गिरती है। वहीं 3.8 किमी लंबी ट्रंक ड्रेन पांच सेक्टर-3 से सेक्टर-16 में जाती है और नजफगढ़ नाले में मिल जाती है। प्रोजेक्ट के तहत नाले के साथ-साथ अब ढकी हुई सीवर लाइन बिछाई जाएगी और सीवर के गंदे पानी को उस लाइन में छोड़ा जाएगा। इसके बाद ट्रंक नाले की सफाई कर इसमें बरसाती पानी का ही बहाव होगा। साथ ही नाले के आसपास फुटपाथ व ग्रीन बेल्ट विकसित करेंगे।

### बनाए जाएंगे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट

सीवर के गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए डीडीए द्वारका सेक्टर-8 स्थित मलेरिया इस्टिट्यूट के पास, द्वारका सेक्टर-19 में फुटबाल स्टेडियम के पास व द्वारका सेक्टर-3 स्थित एनएसआईटी के सामने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित कर रहा है। द्वारका सेक्टर-8 में पांच मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का एसटीपी लगाया जा रहा है। जबकि सेक्टर-19 में सात मिलियन लीटर प्रति दिन क्षमता और सेक्टर-3 में 9.5 मिलियन लीटर प्रति दिन क्षमता का एसटीपी लगेगा। अधिकारियों ने बताया कि ट्रंक ड्रेन दो का गंदा पानी सेक्टर-8 व 19 में जाएगा, जबकि ट्रंक ड्रेन पांच का गंदा पानी सेक्टर-3 स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाया जाएगा।

## डीडीए : फ्लैट्स की कोई नई स्कीम नहीं, पेंटहाउस आएं दिवाली पर

■ विस, नई दिल्ली: डीडीए अपनी पिछली कई स्कीमों का हाल देखकर नए फ्लैट्स वाली स्कीम को जल्दी लाने के मूड में नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, इस समय डीडीए की प्राथमिकता बचे हुए फ्लैट्स को बेचना है। इस बीच लंबे समय से पेंटहाउस का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। पेंटहाउस वाली स्कीम को दिवाली के आसपास लाई जा सकती है। द्वारका में डीडीए के पेंटहाउस तैयार हो रहे हैं। कोविड की वजह से इनके कामों में देरी हुई। अब काम अंतिम चरण में चल रहा है।



डीडीए को 2014 की स्कीम के बाद अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अगस्त, 2022 तक डीडीए के करीब 15500 फ्लैट्स तैयार थे और इन्हें खरीददार नहीं मिल रहे थे। वहीं, पुराने बने हुए फ्लैट्स को बेचने के लिए डीडीए ने नियमों में बदलाव भी किए हैं। पहले आओ-पहले पाओ के तहत भी काफी फ्लैट्स बिके हैं। पेंटहाउस के लिए करीब चार साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। द्वारका सेक्टर-19 में पेंटहाउस और सुपर एचआईजी फ्लैट तैयार हो रहे हैं। डीडीए पहली बार पेंटहाउस स्कीम लेकर आ रहा है। तैयार होने के बाद पेंटहाउस की कीमत का आकलन किया जाएगा। अभी कीमतें तय नहीं की गई हैं। यह फ्लैट ग्रीन बिल्डिंग के तहत तैयार होंगे।

डीडीए को साल 2014 की स्कीम के बाद नहीं मिला है अच्छा रिस्पॉन्स डीडीए की प्राथमिकता बचे हुए फ्लैट्स को बेचना है



NAME OF NEWSPAPER

# Floodplain As Eviction Deadline Looms Large

## DDA Officials Say Will Proceed As Per NGT Orders

Ridhima Gupta

@timesgroup.com

**New Delhi:** More than 2,000 slumdweller of Bella Estate Moolchand Basti on the Yamuna floodplain near Rajghat are on protest, demanding protection from eviction or rehabilitation if they leave the site. On Wednesday, Delhi High Court directed the residents to vacate their jhuggis within three days, failing which they would have to pay Rs 50,000 each to DUSIB or DDA would demolish their shanties.

The panicked slumdweller, who claim to be area residents since the British era and have pleaded their case with the lieutenant governor, chief minister, even the PM, are at their wits' end. To add to their discomfiture, DDA officials insisted the eviction process would proceed as per the orders of the National Green Tribunal disallowing constructions on the Yamuna floodplain. DUSIB officials also claimed that the slum was not listed as an identified JJ camp and, therefore, the residents weren't eligible for relief or rehabilitation.

There are two camps in Bella Estate Moolchand Basti. While the high court ordered the vacation of land in one camp, the hearing in the other case is pending. Randeer, 44, who belongs to the group whose petition was rejected by the court, said, "We have been farming on the riverbank for generations. In fact, our forefathers started farming here because of the water and they paid lagaan (tax) to the British. We have receipts for the same."

Randeer said the residents had voter cards and Aadhaar cards showing their home address in the area. "Yet the government is calling us outsiders and evicting us," he grumbled. "NGT says we are destroying the Yamuna floodplain. It's not us but industries that are dumping waste into the river. We are farmers, we protect the river belt because it feeds us."



Photos: Piyal Bhattacharjee



The panicked slumdweller have pleaded their case with the LG

Heera Lal, 40 one of the petitioners in the pending case, added, "The government earlier took our lands saying they needed to build flyovers. Now they are saying our houses are illegal." He said most men in the camp were either farmers or daily wage workers. "We cannot afford court cases, but we knocked on the door of the courts seeking justice. Only to be disappointed."

While DUSIB says the Bella Estate Moolchand Basti camps are not notified as slums, DDA officials said that there is no rehabilitation possible in cases of illegal construction, which is what NGT says any construction on the Yamuna floodplain is. Lal said, "Around 35 families whose houses were razed earlier by DDA were promised rehabilitation. Many of them also paid Rs 7,000 to DDA for a flat, which they have never got possession of till date."

The residents have been on protest for a year now. After finishing the morning chores, Dulari Devi, 50, her daughter-in-law and grandchildren sit with other women slumdweller on a silent dharna. "Police aren't permitting us to protest on the roads, but we have been sitting here in protest for a year and no one pays any attention to us," said Devi. Another slumdweller, Rekha, 40, who is Bhartiya kisan Union (Balraj)'s Delhi women's president, said, "The law should be equal for everyone. Unfortunately, for the poor, it is not. We are ready to give up our land if it is illegal occupation. But at least provide us rehabilitation."

Five-month pregnant Seema declared her determination to fight for the right to rehabilitation and Sheela bristled, "Enough is enough. Let them throw us on the roads. We will die protesting."



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नई दिल्ली, 19 मार्च, 2023 दैनिक जागरण DATED-----

## अतिक्रमण के मामले पर एलजी के निर्देश के खिलाफ आई लोक निर्माण मंत्री आतिशी

पीडब्ल्यूडी से अपने आदेश मानने को कहा

वी के शुक्ला • नई दिल्ली



मंत्री आतिशी •

राजनिवास और दिल्ली की सरकार के बीच तनातनी जारी है। दिल्ली की लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने अतिक्रमण के मामले में पीडब्ल्यूडी को उनके स्वयं के आदेश को मानने के लिए कहा है। 17 मार्च को जारी आदेश में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीडब्ल्यूडी अतिक्रमण हटाने की कोई भी कार्रवाई करने से पहले विभाग की मंत्री की अनुमति लेगा। पिछले तीन माह में यह दूसरी बार है जब दिल्ली सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया है।

उपराज्यपाल के निर्देश पर विभिन्न विभागों द्वारा दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पीडब्ल्यूडी दिल्ली में अपनी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। कुछ समय पहले सलीमगढ़ किला के पास अवैध धार्मिक निर्माण हटाए गए हैं। इसी तरह बहादुर शाह जफर मार्ग पर भी कुछ समय पहले मंदिर और मस्जिद के सामने से अतिक्रमण हटाया गया है। यह कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच

### हो चुका है विवाद

जनवरी में आरके पुरम, महारौली, धौला कुआं में झुग्गियां हटाने की कार्रवाई के आदेश को लेकर विवाद हुआ था। डीडीए ने वहां अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए थे, कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाया भी गया था। उस समय आप नेताओं ने इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार और एलजी को जिम्मेदार ठहराया था, वहीं भाजपा नेताओं ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए थे।

शुक्रवार को लोक निर्माण मंत्री का आदेश सामने आया है। आदेश में मंत्री ने कहा है कि उनकी जानकारी में आया है कि विभाग सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। बिना मंत्रालय की जानकारी के अतिक्रमण हटाया जा रहा है।

### दिल्ली सरकार ने पूछा, किसके आदेश पर तोड़े गए हैं रैन बसेरे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बेघरों के लिए आठ रैन बसेरों को हाल ही में तोड़े जाने के लिए शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की आलोचना की है। सरकार ने कहा है कि यह कार्रवाई अमानवीय है जो सरकार की अनुमति के बिना की गई है। दिल्ली सरकार ने इसे लेकर डूसिब को पत्र लिखा है और पूछा है कि यह कार्रवाई किसके आदेश पर की गई। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डूसिब को लिखे पत्र में कहा है कि मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि कश्मीरी गेट आइएसबीटी के पास आठ रैन बसेरों को गत 10 मार्च की रात को ध्वस्त कर दिया गया है। यहां रह रहे लोगों को बिना कोई पूर्व सूचना दिए यह किया गया है। डूसिब के अधिकारियों ने बिना किसी सूचना और बगैर सरकार की अनुमति के यह फैसला लिया है। लगभग 1,185 लोग बेघर हो गए थे। जबकि

डूसिब को लिखा पत्र, कहा कार्रवाई है अमानवीय, अधिकारियों ने सरकार की अनुमति के बिना की कार्रवाई

इस आश्रय स्थल का हाल ही में एलजी द्वारा निरीक्षण किया गया था। बेहतर तरीके से इसका विस्तार करने के लिए एक बड़ा निवेश किया गया था। एकाएक सुविधाएं ध्वस्त कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई करने से पहले न तो बोर्ड के उपाध्यक्ष और न ही बोर्ड के अध्यक्ष को जानकारी दी गई। पत्र में पूछा गया है कि आश्रयों का निर्माण कब हुआ और इनके निर्माण और जीर्णोद्धार पर अब तक कितना व्यय किया गया है। सौरभ ने लिखा कि डूसिब के निदेशक ने इंटरनेट मीडिया पर कहा है कि विध्वंस दिल्ली सरकार के आदेश पर किया गया है। इस पर डूसिब यह बताए कि इसके लिए दिल्ली सरकार से किसने निर्देश दिए हैं।



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **दैनिक जागरण नई दिल्ली, 19 मार्च, 2023** DATED-----

## पुरानी दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों को नरेला ले जाने पर फंसा पेच, नहीं मान रहे प्रस्ताव होलंबी कला में दिए जा रहे प्लॉट को ट्रांसपोर्टरों ने बताया साइज में बहुत छोटा

नेमिष हेमंत • नई दिल्ली



राजधानी की सड़कों पर माल से लदे खड़े ट्रक • जागरण आर्काइव

कमला नगर, सदर बाजार व खन्ना मार्केट समेत पुरानी दिल्ली के अन्य प्रमुख बाजारों में स्थित 1200 से अधिक ट्रांसपोर्टरों के व्यवसाय को नरेला में स्थानांतरित करने के प्रयास में पेच फंसा गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा इन्हें नरेला के होलंबी कला में मुहैया कराए जा रहे प्लॉट को लेकर कई आपत्तियां उठाते हुए ट्रांसपोर्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं।

हाल ही सिविल लाइंस में एक बड़ी बैठक में एक मत से उन्होंने डीडीए के प्रस्ताव को नहीं मानने का निर्णय लिया है। साथ ही इसे लेकर आगे की गतिविधियों की रोकते हुए डीडीए अधिकारियों से बैठक का वक्त मांगा है। इस मामले को लेकर जल्द ही डीडीए अधिकारियों की बैठक में विमर्श कर नया प्लान तैयार किया जा सकता है, क्योंकि उसे भी मौजूदा प्लान में विसंगतियां समझ आई हैं। फिलहाल डीडीए ने 125 ट्रांसपोर्टरों को प्लॉट के लिए धन जमा करने के लिए पत्र भेजा है।

पुरानी दिल्ली से थोक बाजारों को दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के क्रम में यहां के ट्रांसपोर्टरों को भी नरेला में ट्रांसपोर्ट हब देने पर चर्चा वर्ष 2004 से चल रही है, तब



हमें वहां मात्र 50-50 मीटर का प्लॉट दिया जा रहा है, जो गोदाम व लोडिंग-अनलोडिंग के

लिहाज से कम है। ऊपर से उसकी दर अधिक है। यह चावडी बाजार के पेपर व तिलक बाजार के रासायन कारोबारियों से दोगुनी है। इसलिए आपत्ति जताई है और डीडीए अधिकारियों से मिलने का वक्त मांगा है। - **परमीत सिंह गोल्डी**, अध्यक्ष, दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन



ट्रांसपोर्ट हब का जो लेआउट प्लान बनाया गया है, उसमें भी विसंगतियां हैं। दोनों तरफ गोदामों के बीच

18 मीटर की सड़क दी जा रही है, यह चौड़ाई काफी कम है। इसी तरह की अन्य विसंगतियां हैं। दूसरे, डीडीए का कहना है कि पुरानी दिल्ली में बुकिंग ऑफिस भी बंद करें। यह कैसे संभव है। **राजेंद्र कपूर**, अध्यक्ष, दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट आर्गनाइजेशन

### मुख्य आपत्तियां

- ट्रांसपोर्टरों की मुख्य आपत्ति यह है कि पुरानी दिल्ली में वर्तमान में मौजूद 1200 से अधिक ट्रांसपोर्टरों में से केवल 200 को ही वहां जगह मिल सकती है, क्योंकि उसका आकार छोटा है। उसमें भी पुरानी दिल्ली में मौजूदा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बदले उन्हें 50-50 मीटर के प्लॉट दिए जा रहे हैं और उसके बदले 33-33 लाख रुपये राशि मांगी जा रही है, जो गलत है।
- जबकि ट्रांसपोर्टर होलंबी कला में गोदाम और पुरानी दिल्ली के बाजारों में बुकिंग ऑफिस रखना चाहते हैं। जबकि डीडीए चाहता है कि वे यहां से पूरी तरह से कारोबार बंद कर दें।
- इसी तरह ट्रांसपोर्ट हब के लिए आवंटित स्थान पर आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं हुआ है। साथ ही हब का जो नक्शा तैयार किया गया है। उसमें भी विसंगतियां हैं।

हाई कोर्ट ने बाहरी दिल्ली इलाके में एक ट्रांसपोर्ट हब बनाने का आदेश दिया था। आदेश में ट्रांसपोर्टरों के गोदाम की जगह देने की बात

थी, ताकि सामानों की लोडिंग-अनलोडिंग वहाँ हो सके और इसके लिए ट्रकों को दिल्ली में नहीं आना पड़े। 2010 से यह प्रक्रिया कागजों

में आई और डीडीए ने पुरानी दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों का सर्वे किया था, तब एक हजार से अधिक ट्रांसपोर्टरों का पंजीकरण किया गया था।



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-----DATED-----

\* SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI  
MARCH 19, 2023

# DDMA talks quake, flu to keep city ready for crisis

## Key Buildings To Be Strengthened, Hospitals To Be Identified

Atul.Mathur@timesgroup.com

**New Delhi:** Lieutenant governor VK Saxena on Saturday asked the agencies concerned to retrofit all important buildings as per Earthquake Resilient Building Code and identify hospitals in every district and sub-division for emergency response to mitigate the disaster in case strong tremors hit the national capital.

Sitting in Zone IV, which has a fairly high seismicity, Delhi falls in a "high risk" area. Held in the wake of the disastrous earthquakes in Turkey and Syria last month, the meeting took stock of the city's preparedness in case there is a natural disaster.

The prevalent situation of H3N2 flu, H1N1 flu and Covid-19 was also discussed in the meeting and officials suggested that though not mandatorily, protocols such as masking, physical distancing, hand hygiene and sanitation, and preparedness of hospitals were needed to be followed.

Recounting his experience of the Gujarat earthquake that had caused widespread destruction, the LG said that Delhi needed to be fully prepared to handle any disaster and preparations to this effect should be put in place from today itself.

"Since the housing pattern in Delhi is not in accordance

### TAKING STEPS FOR EMERGENCY RESPONSE

> Retrofitting of all **schools, hospitals, police stations, critical government offices and vulnerable buildings**, especially in Special Area and Old Delhi localities, as per Earthquake Resilient Building Code



> Identification of open spaces for **rescue operations**



> Identifying **hospitals in all districts and sub-divisions** for emergency response



> Widening of narrow lanes and bylanes to ensure access to **ambulances, fire tenders and rescue teams**



> Establishing connectivity with **railway telephone network** to ensure communication if other means collapse



> Compilation and tabulation of all reports and recommendations by **different committees to mitigate disasters**



with the building codes, it makes residents extremely vulnerable in the event of an earthquake of even relatively higher magnitude. It is further compounded with the fact that approaches of these colonies are extremely narrow making movement of people and vehicles almost impossible in cases of such disasters," the LG, who is also the chairman of DDMA, said in the meeting.

Identification of open spaces across the city for rescue operations in the event of an earthquake, broadening of narrow lanes and bylanes to ensure easy access for ambulances, fire tenders and rescue teams and establishing connectivity with railway telephone networks to ensure com-

munication if other means collapse were also discussed.

The LG suggested effective disaster management plans in consultation with all stakeholders, carrying out awareness campaigns on a regular basis, regular mock drills, enhancing the capacity of disaster management teams through training and use of technology to improve actions during disasters efficiently.

"CM Arvind Kejriwal stressed upon the need to compile and tabulate all reports and recommendations of different committees for the mitigation of disasters and their aftereffects. He underlined that once all reports were collated and compiled along with the actions taken

on them so far, the future course of action may be decided," said an official.

Kejriwal is the vice-chairman of DDMA.

Officials said the divisional commissioner, who is also the convenor of DDMA, has been asked to collate all previous reports and recommendations and table them in the next DDMA meeting.

DDMA officials suggested that Delhi should also have its own state disaster relief force, which works in tandem with the national disaster relief force in case of an emergency.

Officials said DDMA was also asked to augment the number of volunteers under the 'Aapda Mitra' scheme, train them and make their information readily available on the websites for access by people in need of any assistance during a disaster. There are currently 1,800 volunteers registered under the scheme in the city.

The meeting was also attended by finance and revenue minister Kailash Gahlot, chief secretary Naresh Kumar, senior officers of Delhi Police, home secretary, DDA vice-chairman, MCD commissioner, all district magistrates and top representatives of Army, National Disaster Management Authority, National Institute of Disaster Management and National Institute of Seismology.



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS: नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | सोमवार, 20 मार्च 2023

## CM के खिलाफ BJP ने किया प्रदर्शन, पुलिस से भी हुई धक्कामुक्की

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

रोहिणी में स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और रोहिणी के विधायक विजेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे और पोस्टर बैनर लेकर स्कूल के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्कामुक्की भी हुई। पार्टी का दावा है कि विजेन्द्र गुप्ता समेत कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है। कई कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हटाया।

विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि उनके प्रयासों की बदौलत ही डीडीए ने इस एरिया की एक लाख से अधिक आबादी को देखते हुए यहां स्थानीय लोगों के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने के लिए दो एकड़ जमीन अलॉट की थी। मगर अब दिल्ली सरकार ने एक सामान्य स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय का नाम देकर उसमें रोहिणी सेक्टर-18, 19 और आस-पास के अन्य इलाकों में रहने वाले आम लोगों के बच्चों के दाखिले पर रोक लगा दी है। इससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी

■ एक सामान्य स्कूल को एक्सिलेंस स्कूल का नाम देकर उद्घाटन करने का आरोप  
■ कहा, स्थानीय बच्चों को नहीं मिल पाएगा एडमिशन

है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर गरीबों के बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि नियमों के अनुसार बच्चों को उनके घर के आस-पास ही एजुकेशन मिलनी चाहिए। इस विधानसभा क्षेत्र के हर सेक्टर में एक सरकारी स्कूल है, लेकिन दिल्ली सरकार सेक्टर-18, 19, राजा विहार और आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले बच्चों से इस सुविधा को छीनकर उन्हें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर कर रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 'उत्कृष्ट विद्यालय' के लिए किसी अन्य जगह पर नई इमारत बनाएं और इस स्कूल को उसके मूल स्वरूप में बहाल करें, ताकि स्थानीय निवासियों के बच्चे इसमें दाखिल पा सकें। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने इस बारे में जल्द कोई फैसला नहीं लिया, तो वे प्रदर्शन को और तेज करेंगे। उन्होंने दावा कि विरोध प्रदर्शन को देखकर सीएम को पिछले दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा।



बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे और पोस्टर बैनर लेकर स्कूल तक पहुंचे थे

## कालकाजी मंदिर में नवरात्र के लिए HC ने जारी किए निर्देश



प्रशासनिक अधिकारियों में काम बांटे गए

Prachi.Yadav@timesgroup.com

■ साउथ दिल्ली स्थित सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर के पुनर्विक्रम की योजना के बीच 22 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्र को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए पुलिसकर्मियों को पर्याप्त संख्या में तीन शिफ्ट में लगाया जाए। आदेश के मुताबिक बैरिकेड के जरिए भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी, ताकि किसी भी तरह की भगदड़ या भारी भीड़ वाली स्थिति न बने। अन्य निर्देशों में इमरजेंसी

के लिए दो एंबुलेंस और दो फायर ब्रिगेड को वहां लगाना शामिल है। दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट और एसडीएम, कालकाजी को दो शिफ्ट में 100-100 सिविल डिफेंस वॉलंटियर, एक डॉक्टर और दो पैरामेडिक्स की व्यवस्था करने का काम दिया गया है।

मंदिर परिसर में पर्याप्त मात्रा में पेयजल और आसपास के नालों में साफ सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड को होगी। नवरात्र में मंदिर के अंदर बिजली की सप्लाई ब्रीकडाउन सुनिश्चित करेगी और इसीब को जरूरी स्टाफ के साथ 16 मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करने का काम मिला है। पीडब्ल्यूडी और डीडीए से कहा गया कि वह आसपास की सड़कों की मरम्मत करवाएं।

### श्रद्धालुओं के लिए

- बैरिकेड के जरिए भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी
- इमरजेंसी के लिए एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की दो-दो गाड़ियां तैनात रहेंगी



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | सोमवार, 20 मार्च 2023

DATED

## दिल्लीवालों को यमुना के किनारे मिलेगा एक नया पिकनिक स्पॉट

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री नगर से गढ़ी मांडू तक 11km हिस्से की बदलेगी सूरत, गंदगी हटाने का चल रहा काम

गढ़ी मांडू में होने वाला पौधरोपण



हाला ही में एलजी ने अपानक निरीक्षण कर काम में तेजी लाने के लिए थे निरीक्ष

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

शास्त्री नगर-बेला फार्म-गढ़ी मांडू के किनारे यमुना बाढ़ क्षेत्र का अंत करवाकर होगा। 11 किलोमीटर का यह हिस्सा उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए नया पिकनिक स्पॉट बनाएगा। एलजी वी. के. रामसेना के निदेश पर 21 मार्च को वन विभाग के साथ मिलकर डीडीए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है। इस हिस्से में विराटन घास के अलगाव बांध और फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही पृथक से यहां की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। साथ ही पूजाल का स्तर भी बढ़ेगा। बीते 11 मार्च को यहां एलजी ने औचक निरीक्षण कर इस जगह से गंदगी हटवाने का काम शुरू करवा दिया था।

इस हिस्से में यमुना किनारे तीन लेयर की हरिखली दिखाई देगी। इसमें पहला हिस्सा विराटन घास का



21 मार्च को वन विभाग के साथ मिलकर डीडीए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है

होगा। दूसरा हिस्सा बांस का होगा और तीसरा हिस्सा फूल और फल्ले के पौधों का होगा। करीब 4.50 लाख स्क्वियर हेक्टेयर की जगह में यह पौधरोपण होगा।

### बांस की खासियत

यहां तीन प्रजातियाँ के बांस लगाए जा रहे हैं। इनमें बंबूच नुशन, बंस टुलख और डेडवुडकलमस शामिल हैं। बांस अन्य पौधों की तुलना में 30 प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बंबूच नुशन सजगंधी प्रजाति है। वहीं, अन्य दोनों कोटिंग इंडस्ट्री में काम आने वाली प्रजातियाँ हैं।

इसमें 2 लाख वर्ग मीटर में बांस, 70 हेक्टर वर्ग मीटर में विराटन घास और 1.80 वर्ग मीटर एरिया में फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। इस क्षेत्र में कुल 13371 फूलों के पौधे लगेंगे। इनमें गुलमोहर, अमलनागर, लैंगुरदंडिया, इरिथिया, टकोमा, जकरंटो, छक और रोसल के पेड़ लगाए जाएंगे। यह पौधे बढ़े होने के बाद 15 से 25 मीटर उंच होते हैं।

### बड़े काम की घास

विराटन घास का बाढ़ क्षेत्र में कामी अग्रम गेल है। अर्थात् ईस्ट की तरह डीडीए यहां भी लेन तरह की विराटन घास लगाएगा। इनमें चम, मुंज और खटोकर शामिल हैं। खटोकर घास अपने शल्लोको की वजह से पानी को रिचार्ज करने में सहायक होती है। साथ ही यह जमीन के प्रदूषक तत्वों को भी सोखती है। इनमें जमीन और पानी बचाने की क्रियात्मक तकनीक में इन्हें महत्व दिया जाता है।

इस प्रोजेक्ट में नूतने अधिकारीयों ने बताया कि प्रोजेक्ट को प्रकृतिक तरीके से ही पूरा किया जाएगा। यहां पर इस तरह का पहला नैचुरल किंग्डम जगह है। जिसे यहां पक्षी भी बड़े। इस किस्म में दो इलाकों का काम भी डीडीए कर रहा है। इन इलाकों में पूरे मास पानी रहे इसके लिए नहर के जर्जि इन्हें शामिल में जोड़ा जा रहा है।

पेड़	संख्या	जगह (वर्ग मीटर)
गुलमोहर	548	8772.39
लैंगुरदंडिया	1279	20,462.96
इरिथिया	2469	39,509.99
टकोमा	640	10,245.94
अमलनागर	5,524	88,378.39
जकरंटो	877	14,039.54
छक	407	-
<b>बांस</b>		
बंबूच नुशन	32,691	32,690.85
बंस टुलख	19,228	19,228.25
डेडवुडकलमस	18,321	837.26
<b>घास</b>		
चम	1,38,075	67,656.60
मुंज	1,39,604	68,405.87

## सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के लोगों को मिलेंगे 3 विकल्प

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए अब रॉडवेलवैलमैट का काम चल रहा है। यहां रहने वाले लोगों को तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं और इनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। डीडीए के मुताबिक कोशिश है कि न तो सरकार को नुकसान हो और न लोगों को यह विकल्प महंगे पड़े।



अब डीडीए इसके रॉडवेलवैलमैट पर काम कर रहा है

लोगों के लिए बायबैक पहला विकल्प होगा। इसमें रहने वाले लोगों ने जिस फ्रीमन पर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट लिए हैं उन्हें दूसरी जगह फ्लैट लेने का विकल्प मिलेगा। यदि फ्लैट की कीमत अधिक होगी तो यह अंतर लोगों को चुकाना होगा। इसके अलावा लोगों के पास दूसरा विकल्प रेंटल अपार्टमेंट का होगा। यानी लोग रेंट पर रह सकेंगे और उन्हें डीडीए रेंट उपलब्ध करवाएगा। तीसरा विकल्प डीडीए के खाली फ्लैट्स का होगा। फ्लैट के साइड के अनुरूप ही लोगों को फ्लैट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे।

एक अनौपचारिक कार्यक्रम के तहत डीडीए के अधिकारी ने यह बात बताई। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में प्रस्तावक को

जॉब चल रही है। मुम्बई नगर में बने इस अपार्टमेंट का दरकर करके कमजोर है। यह अपार्टमेंट 2007-09 में बना था और 2011-12 में यह लोगों को आर्बिट्रियर किया गया। कुछ ही समय बाद इस अपार्टमेंट को अमूर्तित घोषित कर दिया गया। इसमें 336 एचआईजी और एमआईजी फ्लैट्स हैं। निर्माण के दो से तीन साल बाद ही यह अस्तित्व में आया। इस पर एलजी ने संज्ञान लेते हुए 24 जनवरी को निर्देश दिया था कि लापरवाह अधिकारियों, कॉन्ट्रैक्टरों, बिजनेस और कन्स्ट्रक्शन एजेंसी के खिलाफ आपराधिक मामलों दर्ज करवाने के साथ प्रस्तावक को जॉब भी करावाई जाए। अब डीडीए इसके रॉडवेलवैलमैट पर काम कर रहा है।



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI  
MONDAY, MARCH 20, 2023

## Grasses, bamboos and flowering trees to infuse life into floodplain

Kushagra.Dixit@timesgroup.com

**New Delhi:** To restore and rejuvenate an 11km stretch of Yamuna floodplain in northeast Delhi, the Delhi Development Authority, in coordination with the forest department, is working on a unique triple-grid plantation programme.

Under this project, a network of selected species of riverine grasses, bamboos and trees will be planted in a manner that helps conserve soil and water, avoids erosion and recharges the groundwater, besides reducing siltation and increasing the floodplain's tolerance to heavy metals.

A stretch covering Shastri Nagar, Bela Farm and Garhi Mandu will be taken up for this purpose.

Over 4 lakh saplings of riverine grasses, 70,000 bamboo

and 13,500 saplings of different kinds of flowering trees will be planted on the floodplain, which will rehabilitate the degraded soil, recharge the groundwater and improve the aesthetics of the area, while maintaining the ecological character of the floodplain," a DDA official said.

The drive will commence on Tuesday and is part of the Yamuna rejuvenation drive.

"We have already started cleaning the floodplain and the riverbanks by removing garbage, C&D waste and encroachments. LG VK Saxena is personally monitoring the project and inspected the site last week," a DDA official involved with the project said.

Officials said that unlike previous attempts, this project would aim to rejuvenate the floodplain through the

universal principles of ecological restoration.

"We are restoring natural depressions, creating catchment zones, reviving floodplain forests and grasslands and creating favourable habitats, especially for water and terrestrial birds," the official said.

"Cleaning/desilting, restoration and maintenance of the two main waterbodies will also be done by DDA on the banks, with the aim of ultimately interconnecting all the waterbodies at different locations through a channel. This interconnectivity will ensure uniform water levels," he added.

In the triple grid layered design, the first layer will be of grasses, followed by bamboo and then flowering and fruit-bearing trees.

"In the first phase, plantation will be carried out over

4.5 lakh sq m of land. We are using flowering and ornamental trees like gulmohar, amaltas, etc. These trees grow up to a height of 15 to 25 meters and will not only help increase the green cover, but also enhance the aesthetics of the floodplain," the official added.

Three species of bamboo are being planted on this stretch as they are known for high water retention, soil conservation and oxygen emission. "While Bambusa nutans is essentially an ornamental species, Tulda and Dendrocalamus are used as raw materials in cottage industries. Riverine grasses are critical for restoration of the floodplain. Munja grass is a perennial grass species and, once planted, its roots don't die for 24-30 years after spreading and helps prevent soil erosion," the official said.

### TRIPLE-GRID PLANT COVER

#### THE PLAN

- > Three types of plantations to be done over 11km along the Yamuna floodplain
- > Floodplain from Shastri Nagar to Garhi Mandu to be rejuvenated
- > A layer each of riverine grass, bamboo and trees to be planted
- > Physical cleaning of plain by removing garbage and waste already underway
- > DDA to implement, forest department to help; work being done under Yamuna rejuvenation drive supervised by the LG



#### Trees | 13,371 saplings

Species | Gulmohar, lagerstroemia, erythrina, takoma, amaltas, jakrada, dhak, semal

Why | Flowering trees reach a height of 15-20 metres; will help in increasing green cover and enhancing the aesthetics



Area  
1.8 lakh sqm

#### Riverine grass | 4,07,475 saplings

Species | Kas, munja, vertiver

Why | Critical for restoration of the floodplain; low-cost solution for soil and water conservation; recharge groundwater; reduce siltation of drainage systems and waterbodies; manage polluted soil; tolerate high level of heavy metals; and prevents soil erosion

Area  
70,000 sqm

#### Bamboo | 70,240 saplings

Species | Bambusa nutans, bambusa tulda, dendrocalamus

Why | High water retention, soil conservation; emit 30% more oxygen than other plants; besides being ornamental, species used as raw material in cottage industries

Area  
2 lakh sqm

